

**Paradeep Port Project**

\*1724. **Shri P. K. Deo:**  
**Shri K. P. Singh Deo:**  
**Shri Srinibas Misra:**  
**Shri Chintamani Panigrahi:**

Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) whether the Government of Orissa have asked the Central Government to reimburse the amount spent by the former in the construction of the Paradeep Port since the Central Government took over the Paradeep Port Project;

(b) if so, the reasons for not reimbursing the amount; and

(c) whether Government are aware that it has upset the Fourth Five Year Plan of the Orissa Government?

**The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai):**

(a) Yes, Sir.

(b) The Government of India did not at any time undertake to finance the Paradeep Port Project. In fact, the State Government embarked on the project without the approval or the concurrence of the Government of India. As the State Government could no longer finance the project, the Central Government, on the request of the State Government, took it over on 1st June 1965.

Further, even though there was no commitment at any time on the part of the Central Government to finance the Paradeep Port Project, the Government of India have already accommodated the State Government by granting loans equivalent to their total investment in the project.

The interest liabilities of the State Government in respect of this loan were duly taken note of by the Fourth Finance Commission in making necessary financial adjustments.

(c) The outlays on the Fourth Plan are related to the availability of re-

sources both at the Centre and in the States, and the final figures for these over the Plan period are still to be decided.

**उत्तर प्रदेश की विद्युत् सम्बन्धी आवश्यकता**

\* 1725. श्री मोलहू प्रसाद :  
 श्री महाराज सिंह भारती :  
 श्री रवि राय :  
 श्री एस० एम० जोशी :  
 श्री राम चरण :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में विद्युत् की आवश्यकता को देखते हुए वहां चौथी पंचवर्षीय योजना की श्रवण के अन्त में 1454 मैगावाट बिजली की कमी रहेगी;

(ख) क्या यह भी सच है कि इसके परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश सरकार उद्योगों और कृषि की तथा अन्य आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकेगी;

(ग) यदि हां तो क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश सरकार को 1500 से 2000 मैगावाट तक अधिक बिजली पैदा करने के लिये सहायता देने का है; और

(घ) यदि नहीं तो इसके कारण क्या हैं ?

सिंचाई और बिजली मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) से (घ). चतुर्थ वार्षिक बिजली सर्वेक्षण के अनुसार चतुर्थ योजना के अन्त में उत्तर प्रदेश की बिजली की मांग 1538 मैगावाट होगी। इसके प्रति चतुर्थ योजना के अन्त तक उत्तर प्रदेश में बिजली की कुल प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता 2071 मैगावाट प्रत्याशित है जिसमें 1482 मैगावाट की वास्तविक क्षमता होगी। इस प्रकार 56 मैगावाट की कमी होने की संभावना है। इस कमी को दूर करने के उपायों पर पंचम् वार्षिक बिजली सर्वेक्षण की रोशनी में विचार किया जायेगा। यह सर्वेक्षण अब हो रहा है।